पिछवाड़ा (बैकयार्ड) मुर्गी पालन द्वारा महिला सशक्तिकरण

प्रज्ञा भदौरिया, रोहित गुप्ता[1] एवं वाई.एस. जादौन[2]

भा.कृ.अनु.प.- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, लुधियाना
[1]कृषि विज्ञान केन्द्र, जालंधर, पंजाब
[2]गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (गडवासू), लुधियाना, पंजाब

भारत में पिछवाड़ा प्रणाली के तहत मुर्गीपालन अपनी सभ्यता के साथ ही प्रारम्भ हुआ है। लाल मिट्टी के जो संकेत मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा से मिले, उनसे प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वजों ने घरेलू 'लाल जंगली मुर्गी' जो अभी भी कश्मीर से लेकर असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विशाखापटनम और आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, उन्हें सभ्यता के आरम्भ से ही पाला जा रहा है। आम-तौर पर ग्रामीण परिवार कुछ स्वदेशी मुर्गियों (5 से 20) को पालते आ रहे है। इसे 'फेमिली पोल्ट्री', 'स्मॉलहोल्डर पोल्ट्री', 'स्कावेंजिंग पोल्ट्री' या 'ग्राम पोल्ट्री' कहा जाता है जो प्रारम्भ से ही अधिकतर महिलाओं द्वारा की जाती रही है। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पोल्ट्री फार्मिंग कुल अंडे के उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देती है। पिछवाड़ा मुर्गीपालन देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है।

वर्तमान परिदृश्य में पिछवाड़ा मुर्गीपालन, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण, अत्यधिक पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए एक सस्ते और उचित स्रोत के रूप में उभर कर आया है। समाज के गरीब लोगों के लिए यह प्रणाली अतिरिक्त आय प्रदान करती है। चूंकि इस प्रणाली में मुर्गी बड़े पैमाने पर बगीचे, गांव-गलियों और खेतों के आसपास के इलाकों में घूम कर फसल अवशेषों, कीड़ों, और चारा सामग्री से भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इनसे उत्पन्न होने वाले अंडे और मांस लगभग कार्बनिक होते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं के बीच उच्च मांग होने के कारण बाज़ार में इनकी अच्छी कीमत मिलती है। अतः ये कहा जा सकता है कि पिछवाड़ा मुर्गीपालन, जिसका राष्ट्रीय अंडा उत्पादन में लगभग एक छोटा सा ही योगदान है, परंतु ये ग्रामीण जनता की आय, रोजगार और पोषण की स्थिति में सुधार के

साथ-साथ सामुदायिक विकास, लिंग सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अति महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाएं भारत की जनसंख्या का लगभग पचास प्रतिशत हिस्सा हैं। आज समाज की महिलाएं बढ़-चढ़ कर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की गतिविधियों में जिम्मेदारी से भाग ले रही हैं। यद्यपि कृषि और ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान सर्वमान्य है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाएं अभी भी अशिक्षित, अकुशल और अज्ञानी हैं। आजादी के बाद से ही भारत सरकार महिलाओं के विकास और अधिकारों की आवश्यकता पर बल देती आ रही है। उन्हें पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है।

बैकयार्ड फार्मिंग पर ट्रेनिंग लेती महिलाएं

महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो महिलाओं अथवा उनके समूहों की क्षमताओं को बढ़ाती है ताकि वो सर्वोत्तम का चयन कर सकें और इस चयन को वांछित कार्यों और निष्कर्षों में बदल सकें। यह एक सक्रिय व बहुआयामी प्रक्रिया है जो उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण क्षमता और शक्ति का अहसास कराने में सक्षम बनाती है। व्यक्तिगत रूप से एक निर्धन महिला न केवल सामाजिक व आर्थिक रूप से निर्बल होती है, अपितु ज्ञान और सूचना जो कि आधुनिक विश्व में विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक हैं, उन तक भी उनकी पहुँच नहीं होती। परन्तु महिलाएं जब एक संगठित समूह में कार्य करती हैं तो वे अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पा सकती हैं। स्वंय-सहायता समूह की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह एक सशक्त संगठनात्मक इकाई है जो समान उद्देश्यों व सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली महिलाओं का समूह है जो स्वेच्छा से अपनी अल्प आय में से छोटी बचत शुरू करते हैं। इनकी संख्या प्रायः दस से बीस तक हो सकती है। सदस्यों द्वारा जमा की गई धनराशि से ये प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण का लेन-देन करती हैं, फिर बैंको से संपर्क स्थापित करती हैं तथा उनसे ऋण प्राप्त करके आय अर्जन करने वाली गतिविधियों का संचालन करती हैं ताकि एक समूह के रूप में इनकी आय में वृद्धि हो सके। पोल्ट्री उत्पादन उद्यम महिलाओं के समूहों के लिए एक संभावित क्षेत्र है जो भारत के ग्रामीण समुदायों में रहने वाली महिलाओं के लिए रोजगार, आय तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। यह महिलाओं के द्वारा उनके घरेलू उत्तरदायित्यों के साथ-साथ पारिवारिक आय में वृद्धि करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। न्यून संतति अंतराल, छोटे निवेश और त्वरित लाभ के कारण महिलाओं के लिए मुर्गीपालन, भेड़-बकरियों और मवेशियों जैसे अन्य पशुओं की तुलना में सबसे आसान व्यवसाय है। इसके साथ ही ये महिलाओं और उनके परिवार के लिए मांस और अंडे के रूप में सस्ते प्रोटीन स्रोत का भी काम करता है।

पिछवाड़ा मुर्गीपालन की विशेषताएँ

पिछवाड़ा मुर्गीपालन में ग्रामीण महिलाओं को अन्य पशुधन उद्यमों की तुलना में अधिक फायदे हैं क्योंकि विविध कृषि-जलवायु में भी मुर्गियों का प्रबंधन करना आसान है। छोटे पैमाने की मुर्गीपालन इकाइयों के लिए भूमि, पूंजी और अन्य बाहरी निवेश की आवश्यकताएं भी न्यूनतम हैं। अच्छी बाज़ार मांग और कीमतों के कारण यह पूरे साल महिलाओं को त्वरित रिटर्न और निरंतर आय प्रदान करता है। देसी मुर्गी से प्राप्त अंडा व मांस व्यापक रूप से उनकी रंजकता, स्वाद और उपयुक्तता के कारण पसंद किया जाता है। देशी मुर्गियां ज्यादातर जंगली, विभिन्न आकार और रंगों की होती है। हालांकि उनकी उत्पादन क्षमता विदेशी मुर्गी से कम होती है, परंतु वे अधिक उपज देने वाली विदेशी मुर्गियों की तुलना में स्थानीय वातावरण में अपनी वरीयता बरकरार रखे हुए हैं तथा अपनी अनुकूलन क्षमता और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता के लिए जानी जाती है। अतः अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में ये मुर्गियां अधिक प्रचिलित हैं। इन पक्षियों को पारंपरिक मुक्त रेंज प्रणाली में सीमित निवेश जैसे कि दाना, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पालन विधि काफी हद तक मुर्गियों की किस्मों, पालन संसाधनों की उपलब्धता, मांस या अंडे के लिए स्थानीय आबादी की पसंद

पर निर्भर करती है। हालांकि प्रबंधन, भोजन और स्वास्थ्य में उचित बदलाव से देसी मुर्गियों का प्रदर्शन भी बेहतर किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण पिछवाड़े मुर्गी पालन के महत्व को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के कई शोध संस्थान और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों ने भी मुर्गियों की विभिन्न प्रजातियाँ मांस, अंडे या दोनों (दोहरे उद्देश्य) के लिए विकसित की है जो कि मुक्त रेंज के कठोर पर्यावरण व कम से कम संभव लागत पर भी अंडे और मांस के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।

मुर्गीपालन शुरू करने से पहले की आवश्यकताएँ

पिछवाड़ा मुर्गीपालन एक ऐसी गतिविधि है जो महिलाएं घर छोड़ने के बिना भी कर सकती हैं और झुंड का प्रबंधन करने के लिए कोई अतिरिक्त समय आवंटित नहीं करना पड़ता है तथा त्वरित और लगातार रिटर्न प्राप्त हो सकता है। चूंकि परिवारों की अधिकांश महिला सदस्य पहले से ही अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक पिछवाड़े मुर्गी उत्पादन की गतिविधियों में लगी हुई होती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसका उचित लाभ नहीं मिला है। अतः कृषक महिलाओं के लिए पिछवाड़ा मुर्गीपालन शुरू करने से पहले वैज्ञानिक जानकारी लेना अच्छा रहता है। इसके लिए महिलाएं कृषि महाविद्यालयों या कृषि विज्ञान केन्द्रों से ग्रामीण पिछवाड़ा खेती पर प्रशिक्षण ले सकती है। फार्म शुरू करने से पहले बाजार की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा छोटी लागत से शुरू करके धीरे-धीरे उसे विकसित करना चाहिए। चूजे हमेशा विश्वसनीय प्रमाणित हैचरी से ही लेने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है सही नस्ल का चुनाव। खेतिहर महिलाओं के लिए उनकी आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार सही प्रकार की मुर्गियों की पहचान करने के लिए स्थानीय उत्पादन प्रणालियों, उनकी सीमाओं और अवसरों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर स्कावेंजिंग नस्ल या एक देशी क्रास का चुनाव करना चाहिए। पिछवाड़ा मुर्गीपालन के लिए वनराजा, ग्रामप्रिया, कारी निर्भीक तथा कारी श्यामा जैसी उन्नत नस्लों को पाल सकते हैं। इस प्रणाली में पक्षियों को रखने के लिए कोई विस्तृत आवास की आवश्यकता नहीं होती है। केवल प्रतिकूल मौसम और शिकारियों से बचाने के लिए रात को मुर्गियों को छोटे कुक्कुट घर और अस्थायी आश्रय प्रदान किए जाते हैं। इन पक्षियों को दिन में खुली प्रणाली में रखा जाता है और रात में केवल लकड़ी या लोहे के पिंजरों में रखा जाता है। ये आश्रय कम लागत वाली सामग्री जैसे बांस, लकड़ी के तख्ते, जाल इत्यादि से आसानी से बनाए जा सकते हैं। देसी मुर्गियों को फलदार वृक्षों के बगीचे में या किसी अन्य छायादार खुले खेत में भी पाला जा सकता है। इसके लिए बाड़े के रूप में बहुत कम कीमत की जाली का घेराव चारों तरफ से बनाना पड़ता है। फीड या खाने के लिए उन्हें ज्यादातर रसोई का कचरा, टूटे हुए चावल, फसल और उसके अवशेषों के साथ अनाज की थोड़ी मात्रा प्रदान की जाती है। पक्षियों को न्यूनतम जैव

तालिका 1: पिछवाड़ा मुर्गीपालन की वित्तीय आवश्यकताएं एवं लाभ (दोहरे उद्देश्य की 10 मुर्गियों के झुंड के लिए)

प्रति परिवार औसत झुंड का आकार (पक्षियों/ मुर्गियों की संख्या)	10
मांस के उद्देश्य के लिए रखे गए औसत पक्षी	04
अंडे के उद्देश्य के लिए रखे गए औसत पक्षी	06
विपणन के समय पक्षी का औसत शारीरिक भार	1.4 कि.ग्रा.
पक्षी का प्रति कि.ग्रा. औसत बाजार मूल्य	600 रु.
मांस उद्देश्य के लिए रखे गए पक्षियों से 1.4 कि.ग्रा. वजन 600 रु. की बिक्री से आय	840 रु.
प्रति परिवार मांस के उद्देश्य के लिए रखे पक्षियों से कुल लाभ (840 रुपए/पक्षी (1.4 कि.ग्रा.) x 4	3360 रु.
वितरण के दिन से 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंडों की औसत संख्या	130
प्रति अंडा औसत बाजार मूल्य	10.00
अंडे/पक्षी से लाभ	1300 रु.
अंडे/प्रति परिवार (1300 x 6) से कुल लाभ	7800 रु.
शुद्ध आय (अंडा+मांस)	11160 रु.

सुरक्षा के साथ रखा जा सकता है और उत्पादों को स्थानीय रूप से या घर में ही उपभोग किया जा सकता है। बेहतर नस्ल को अपनाने के कारण अगर महिलाएं इसको व्यावसायिक रूप भी देना चाहे तो 10 से 15 हजार रुपए की लागत से छोटा सा बांस का फार्म बनाकर मुर्गियां रखकर पालन कर सकती हैं।

पिछवाड़ा मुर्गीपालन से महिलाओं के जीवन पर प्रभाव

अटारी क्षेत्र-1 के कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रयासों के फलस्वरूप पिछवाड़ा मुर्गीपालन से गरीब महिलाओं की आजीविका पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की गरीबी को कम करने, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार पिछवाड़ा मुर्गीपालन महिलाओं को सशक्त बनाने में एक सक्षम कारक है। चूंकि महिलाओं को पक्षियों या अंडों की खरीद और विपणन करते समय विभिन्न लोगों से निपटना पड़ता है, इसलिए इन महिलाओं को धीरे-धीरे आत्मविश्वास प्राप्त होता है और अलगाव से बाहर निकल कर ये सभी समाज में उभर कर आती हैं। इस प्रतिरूप के माध्यम से कई परिवारों को वित्तीय और आर्थिक आजादी प्रदान करने के अलावा समूह गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिली है। पिछवाड़ा मुर्गीपालन में लगे परिवारों को लगभग दैनिक रूप से 10 से 12 रुपए प्रति अंडे की बिक्री करके आय का एक छोटा लेकिन स्थिर साधन प्राप्त होता है। वे जीवित पक्षियों को 600 से 800 रु. प्रति कि.ग्रा. शारीरिक भार (लाइव वजन) के अनुसार बेचकर भी लाभ कमा रहे हैं। महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे इस उद्यम से औसत वार्षिक आय करीबन 11000-12000 रु. प्रति परिवार प्राप्त कर रही है। महिला किसानों को सलाह दी जाती है कि वे चिकन उत्पादन के लिए कुछ अंडे चुन लें ताकि नस्ल का प्रचार किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप ये महिलाएं चूजों को 60-80 रुपये के हिसाब से आस-पास के गांवों में बेचती हैं। इन महिलाओं से प्रोत्साहित होकर और अधिक महिलाएं पिछवाड़े कुक्कुट के क्षेत्र में खुद को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों व कृषि विज्ञान केन्द्रों तक पहुंच रही हैं।

सरकार की पहल

पिछवाड़े मुर्गीपालन को शुरू करने के लिए सरकार भी मदद करती है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सकेंद्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-पशुपालन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से विभिन्न पिछवाड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम और ग्रामीण पिछवाड़ा योजना चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न लाभार्थी उसका फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए कृषि क्षेत्र की महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए कुक्कुट पालन जैसे व्यवसायों में महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राज्य व केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। पिछवाड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम का उदेद्श्य पिछवाड़ा कुक्कुट इकाईयां स्थापित कर लाभार्थियों को रोजगार देना और उनके परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन करना है। विशेषरूप से अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उनके घरेलू उत्तरदायित्यों के अतिरिक्त पारिवारिक आय में वृद्धि करने का यह एक तरीका है। पिछवाड़ा कुक्कुट की एक इकाई के अन्तर्गत लाभार्थी के लिए चूजे, कुक्कुट आहार, निःशुल्क प्रशिक्षण, दवा और चूजों के लिए छप्पर की व्यवस्था करवाई जाती है। यह पूर्णतया अनुदान है, इसमें लाभार्थी से कुछ भी नहीं लिया जाता है। भारत सरकार पिछवाड़ा मुर्गीपालन की क्षमता को समझते हुए तथा जैव-विविधता संरक्षण और आजीविका उत्पादन दोनों के लिए कुक्कुट की विभिन्न स्वदेशी नस्लों को भी बढ़ावा दे रही है जो वित्तीय लाभों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के साथ-साथ कुक्कुट की विभिन्न प्रजातियों को बचाए रखने के लिए भी कारगर साबित हो रही है। वहीं मुर्गीपालन के ऋण में नाबार्ड द्वारा 25 प्रतिशत तक की छूट भी मिलती है। इस प्रकार से सरकार की पहल से खेतिहर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के साथ मुर्गीपालन व्यवसाय को अपनाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं उनके इस कार्य को देखकर अन्य महिलाओं को भी दिशा मिलेगी।

पिछवाड़ा मुर्गीपालन के लाभार्थी